

राजस्व प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर – भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा जी.ओ.आई. से सहायतानुदान सम्मिलित हैं।
पूँजीगत प्राप्तियां	पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा जी.ओ.आई. से ऋणों एवं अग्रिमों के अतिरिक्त लोक लेखा से संभूतियां शामिल हैं।
राज्य कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित ऐसे संगठन/संस्था शामिल होते हैं जो राज्य में किन्हीं विशेष कार्यक्रमों, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के लिये राज्य कार्यान्वयन अभिकरण, एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं।
उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि जी. एस.डी.पी. एक प्रतिशत तक बढ़ती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट्स तक बढ़ जायेगी।
कोर पब्लिक गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव; प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुयें एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।
मैरिट गुड्स	मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुयें हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिये तथा इसलिये उनकी खपत को प्रोत्साहित करना चाहता है। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइज्ड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।

विकास व्यय	व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत लागत और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।
ऋण पोषण	ऋण पोषण, काफी समय तक लगातार ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात कायम करने के लिये राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषणता वर्तमान या सौंपे गये दायित्व की पूर्ति के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता को बढ़ाने से मेल खानी चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर ब्याज दर या सार्वजनिक उधारों की लागत से बढ़ जाती है, ऋण-जी.डी.पी. अनुपात स्थिर रहता है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक है या संयमित ऋणात्मक है। दिये गये दर प्रसार (जी.एस.डी.पी. बढ़ोतरी दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा प्रसार (ऋण दर प्रसार), ऋण पोषण शर्तें बताती हैं कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य हो तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततोगत्वा स्थिर हो जायेंगे। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक में बदल जाता है तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात वृद्धि पर होगा। इसके धनात्मक होने के मामले में, ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात अन्ततोगत्वा गिरेगा।
गैर-ऋण प्राप्तियों की	राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने से है। ऋण पोषण को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।
उधार ली गई निधियों की	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुये उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।

संकेताक्षरों की शब्दावली

ए. एण्ड ई.	लेखा एवं हकदारी
ए.सी.	आकस्मिक सार
ए.ई.	कुल व्यय
ए.आई.ए.	अखिल भारतीय औसत
ए.पी.	अनुमोदित योजना
ए.पी.डी.आर.पी.	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
ए.आर.बी.पी.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आर.जी.एफ.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत परिव्यय
सी.ओ.	पूँजीगत परिव्यय
डी.सी.सी.	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
डी.सी.आर.एफ.	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
डी.डी.पी.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
डी.ई.	विकास व्यय
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.आर.डी.ए.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
एफ.आर.बी.एम.	राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एच.पी.जी.एल.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आई.ए.वाई.	इन्दिरा आवास योजना
आई.पी.	ब्याज भुगतान
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
जे.एन.एन.यू.आर.एम.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
के.जी.बी.वी.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय
एम.आई.एस.	सूक्ष्म सिंचाई स्कीम
एम.पी.एल.ए.डी.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमें
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी

एन.एफ.एस.एम.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एन.जी.ओ.	गैर - सरकारी संस्था
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
एन.पी.ई.जी.ई.एल.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
एन.पी.आर.ई.	योजनेतर राजस्व व्यय
एन.पी.आर.आर.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां
एन.आर.ई.जी.ए.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एन.आर.एच.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
ओ. एण्ड एम.	परिचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
पी.ए.जी.	प्रधान महालेखाकार
पी.सी.सी.ई.	प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय
पी.सी.डी.ई.	प्रति व्यक्ति विकास व्यय
पी.सी.एस.एस.ई.	प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय
पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी.आर.ई.	योजनागत राजस्व व्यय
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.ई.	संशोधित अनुमान
आर.जी.जी.वी.वाई.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना
आर.आर.	राजस्व व्यय
एस. एण्ड डब्ल्यू.	वेतन एवं मजदूरी
एस.ए.आर.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस.जी.आर.वाई.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एस.जी.एस.वाई.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एस.एस.ए.	सर्व शिक्षा अभियान
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्र व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टीएच.एफ.सी. (ते.वि.आ.)	तेरहवां वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण - पत्र
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर